संक्षिप्त समाचार

अधिकारियों ने हटवाई पानी की लाइनों में लगी पांच मोटरें

गरमपानी(नैनीताल), एजेंसी। क्षेत्र में बढ़ती पेयजल समस्या को देखते हुए कोश्याकुटोली के एसडीएम बीसी पंत ने कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को राजस्व विभाग और जल संस्थान की टीम ने गरमपानी और खैरना बाजार में घर-घर जाकर चेकिंग अभियान चलाते हुए पानी की मुख्य लाइन से घरों की लाइन में लगाई गई पांच मोटरों को हटाया। साथ ही लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए पेयजल का व्यावसायिक प्रयोजन और दुरुप्रयोग करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कहीं है। एसडीएम ने बताया कि पेयजल समस्या को दूर करने के लिए अभियान चलाया गया है। इस दौरान राजस्व उपनिरीक्षक विजय नेगी और जलसंस्थान कर्मी मौजूद रहे।

गांवों में पानी के लिए मारामारी

अल्मोड़ा, एजेंसी। जिले के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। गर्मी बढ़ने से पेयजल स्रोतों भी सूखने लगे हैं। ऐसे में पानी के लिए घमासान मचा हुआ है। जल संस्थान ने प्रभावित इलाकों में पेयजल टैंकर और पिकअप भेज कर 50 हजार लीटर पानी बांटा। जिले के जैती, लमगड़ा, कनरा, बल्टा, गुरुड़ाबाज, शीतलाखेत, भेटुली आदि इलाकों में पेयजल समस्या बनी हुई है। पानी के लिए इन क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों को अधिकांश समय पानी का इंतजाम करने में ही बर्बाद हो रहा है। दोपहर की तेज धूप में ग्रामीण प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी ढो कर लाने का मजबूर हैं। बुधवार को सूचना मिलने के बाद जल संस्थान ने प्रभावित इलाकों में पेयजल टैंकर, पिकअप वाहन भेजकर 50 हजार लीटर पानी बांटा। टैंकर पहुंचते ही पानी लेने के लिए लोग खाली बर्तनों के साथ पेयजल टैंकर पर टूट पड़े।

घर में कोई नहीं फिर भी आ गया 34 हजार रुपये का बिल

मौलेखाल (अल्मोड़ा), एजेंसी। सल्ट में यूपीसीएल के एक उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि बगैर बिजली का उपयोग किए ही उसके सही मीटर को खराब बताकर 34 हजार रुपये का बिल थमा दिया गया। उपभोक्ता ने इसका विरोध करते हुए बिल ठीक करने की गुहार लगाई तो यूपीसीएल के अधिकारियों ने उसके साथ अभद्रता की। सल्ट के पीनाकोट निवासी प्रकाश बिष्ट ने कहा कि उसका परिवार लंबे समय से चंडीगढ़ रहता है। उसने अपने पैतृक मकान में बिजली का कनेक्शन लिया है। लंबे समय से घर में बिजली का उपयोग बंद है। घर लौटकर जब वह कनेक्शन कटवाने के लिए मीटर सहित एसडीओ कार्यालय पहुंचा तो मीटर खराब बताते हुए उसे 34,746 रुपये का बिल थमा दिया। बताया कि जब मीटर की जांच की गई तो वह सही मिला और रीडिंग भी बेहद कम निकली। उसने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।

बसें न चलने से अल्मोड़ा डिपो को 60 हजार का नुकसान

अल्मोड़ा, एजेंसी। अल्मोड़ा डिपो की पांच रूटों पर बृहस्पतिवार को बसें नहीं चलीं। पर्यटन सीजन में बस न चलने से डिपो को 60 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज डिपो चालकों की कमी से जूझ रहा है। जिससे सेवाएं बाधित हो रही हैं। बृहस्पतिवार को रोडवेज की टनकपुर, मासी, लमगड़ा-दिल्ली, बेतालघाट-दिल्ली, सायंकालीन अल्मोड़ा-देहरादून सेवाओं का संचालन ठप रहा। बस न चलने से इन रूटों को जाने वाले यात्री और पर्यटक परेशान रहे। इधर, टैक्सियों की किल्लत से समस्या और भी बढ़ गई है। जिससे खास कर ग्रामीण रूटों पर आवाजाही में यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर, रोडवेज डिपो के सहायक महाप्रबंधक विजय तिवारी ने बताया कि बसों को संचालित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

बसें न चलने से अल्मोड़ा डिपो को 60 हजार का नुकसान

अल्मोड़ा, एजेंसी। अल्मोड़ा डिपो की पांच रूटों पर बृहस्पतिवार को बसें नहीं चलीं। पर्यटन सीजन में बस न चलने से डिपो को 60 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज डिपो चालकों की कमी से जूझ रहा है। जिससे सेवाएं बाधित हो रही हैं।

प्रशासन के प्रयासों के बाद भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहे हैं फुटपाथ और बाजार

हल्द्वानी, एजेंसी।
हल्द्वानी में स्थानीय प्रशासन और नगर निगम के तमाम प्रयासों के बाद भी शहर की सड़कें, फुटपाथ और बाजार अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य चौराहों से लेकर मेन रोड और बाजार सभी अतिक्रमण की जद में हैं। फुटपाथ पर भी लोग दुकान सजाए हुए हैं। इसी साल जनवरी में स्थानीय प्रशासन और नगर निगम ने जिस सिंधी चौराहे से आंबेडकर पार्क तक अतिक्रमण हटाया था वहां फिर से खड़े फल-सब्जी के ठेले प्रशासन को चिढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

नैनीताल रोड में एमबीपीजी कॉलेज के सामने सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर अतिक्रमण है। टैक्सी स्टेंड तक यही स्थिति है। कहीं फड़ खोखे लगे हैं तो कहीं फूल से लेकर जूस विक्रेताओं ने कब्जा किया है। नगर निगम दफ्तर, एसडीएम कार्यालय, कोतवाली के सामने से लेकर रोडवेज तक सड़क के दोनों ओर यही स्थिति है।

सरस मार्केट के पास से लेकर चौराहे तक सड़क के एक ओर फुटपाथ पर फलों से लेकर पौधे बेचने वालों ने

कब्जा किया है। चौराहे के सामने फुटपाथ पर कपड़े बेचने वालों की दुकानें सजी हुई हैं।

सिंधी चौराहे से लेकर आंबेडकर पार्क तक प्रशासन ने जनवरी में सड़क चौड़ीकरण के लिए अस्थायी अतिक्रमण हटाए थे। अब चौराहे के दोनों तरफ, होली ग्राउंड और नगर निगम की पार्किंग के सामने फिर से अतिक्रमणकारी काबिज हो चुके हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल के सामने पेड पार्किंग से लेकर एफटीआई गेट तक फुटपाथ पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों फड़ लगे हुए हैं। अस्पताल से पास से पीछे की ओर जाने वाली गली में दोनों ओर खाने-पीने के ठेले लगे हैं। यहां से पैदल गुजरना भी मुश्किल होता है। मटर गली, पटेल चौक, बर्तन बाजार, खानचंद्र मार्केट, मीरा मार्ग, कारखाना बाजार, सदर बाजार से लेकर रस्सी गली तक 20 फुट की सड़क अतिक्रमण के कारण पांच फुट भी नहीं बचती है। रही सही कसर इन बाजारों में ठेले लेकर फेरी लगाने वाले पूरी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार आने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

भूकंप की सूचना पर बचाव कार्य में जुट गया हर महकमा

देहरादून, एजेंसी। चारधाम यात्रा में हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए देहरादून में मॉकड्रिल की गई। जिले में तीन अलग-अलग स्थानों पर तैयारियों को परखा गया। सुबह 9:30 बजे रिक्टर स्केल पर 5.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस होने की सूचना आपदा परिचालन केंद्र से सभी तहसीलों, पुलिस थानों को वायरलेस के माध्यम से दी गई। निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी क्षेत्र में नुकसान की सूचना हो तो आपदा परिचालन केंद्र को सूचित करें। इसके बाद सभी विभाग हरकत में आए और बचाव कार्य में जुट गए। आपदा की सूचना पर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने आपदा कंट्रोल रूम से निर्देश दिए। उन्होंने जीजीआईसी राजपुर रोड एवं दून चिकित्सालय पहुंचकर रेस्क्यू आपरेशन का जायजा लिया। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व रामजी शरण ने पुलिस लाइन रेसकोर्स में पुलिस अधिकारियों के साथ मोर्चा संभाला।

सुबह 09:45 बजे राजकीय बालिका इंटर कालेज राजपुर रोड की प्रधानाचार्य ने फोन कर बताया कि स्कूल भवन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। वहां 30-40 बच्चे व अन्य स्टाफ फंसे हैं। सूचना प्राप्त होते ही उप जिलाधिकारी सदर हरगिरी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ के 20 तथा एनडीआरएफ के 30 सदस्य, एंबुलेंस, फायर टीम, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया। बचाव दल ने सभी व्यक्तियों को रेस्क्यू किया। पांच घायलों को 108 एंबुलेंस सेवा से दून मेडिकल कालेज चिकित्सालय भेजा गया। यहां से तीन सामान्य घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दो गंभीर घायलों को चिकित्सालय में भर्ती किया गया। बचाव दल की ओर से सुबह 10:54 बजे राहत एवं बचाव कार्य पूरा किया गया।

आपदा परिचालन केंद्र पर सुबह 10:17 बजे सूचना प्रसारित हुई कि दून चिकित्सालय की इमरजेंसी बिल्डिंग में आग लग गई है। सूचना प्राप्त होते ही फायर टीम को मौके पर रवाना किया गया। एसडीआरएफ का 10 सदस्यीय दल, फायर की 11 सदस्यीय टीम सहित एसडीआरफ टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू आपरेशन चलाया। प्रातः 10:40 बजे आग पर काबू पाया गया।

तराई में घट रही है कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता

रुद्रपुर, एजेंसी। अच्छी फसल उत्पादन की चाह में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल और जैविक खादों से दूरी मिट्टी की सेहत पर भारी पड़ रही है। तराई की उपजाऊ जमीन से लिए गए मिट्टी के नमूनों में मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई गई है। विभाग की ओर से भारत सरकार के पोर्टल पर जांच रिपोर्ट अपलोड करने की कार्रवाई की जा रही है।

ऊधमसिंह नगर जिले से कृषि विभाग ने 9893 मिट्टी के नमूने लिए थे। इन नमूनों की जांच रुद्रपुर स्थित मंडलीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में की गई थी। इसमें 65 फीसदी नमूनों में पोटाश और 65 फीसदी नमूनों में जीवांश कार्बन की कमी पाई गई है। इसके अलावा 10.98 फीसदी में सल्फर, 29.71 में बोरॉन और 11.28 फीसदी नमूनों में जिंक की कमी पाई गई। नैनीताल जिले में 2502 और पिथौरागढ़ में 3442 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में आए हैं। नैनीताल में 41 फीसदी और पिथौरागढ़ में 25 फीसदी नमूनों में फॉस्फोरस की कमी पाई गई है। मंडलीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के सहायक निदेशक कल्याण सिंह ने बताया कि किसानों को कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैविक खादों का प्रयोग करने को कहा जा रहा है। भारत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के जिलों में एक लाख पांच हजार 70 मिट्टी के नमूनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले यह लक्ष्य 87590 था और फिर लक्ष्य में संशोधन किया गया है। कुमाऊं मंडल की बात करें तो ऊधमसिंह नगर में 11840, नैनीताल में 7560, अल्मोड़ा में 9000 का लक्ष्य रखा गया है।

मानव तस्करी में गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारण -चिदानंद

ऋषिकेश, एजेंसी। परमार्थ निकेतन में रेस्क्यू फाउंडेशन की ओर आध्यात्मिक रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के सदस्यों ने योग, ध्यान, प्राणायाम, हवन, सत्संग, व्यक्तित्व विकास, जिज्ञासाओं का समाधान, गंगा आरती आदि विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग किया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि वर्तमान समय में मानव तस्करी विश्व की प्रमुख समस्याओं में एक है। सभी कोशिशों के बावजूद इसे रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। कोई भी राष्ट्र इस समस्या से अछूता नहीं है। इस दिशा में प्रयास तो किये जा रहे हैं, लेकिन पूर्णतया प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे गरीबी और अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है।

कहा कि सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन, बेहतर जीवन की लालसा, सामाजिक सुरक्षा की चिंता, जागरूकता की कमी जैसे अनेक कारण हैं।

त्यागपत्र वापस लेने को राजी हुए चुघ

गदरपुर, एजेंसी। गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरबंश सिंह चुघ सहित अन्य नामजदों के खिलाफ केस रद्द करने की मांग को लेकर सिख संगठनों की बैठक हुई। इस दौरान हरबंश सिंह चुघ से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष पद से दिए गए इस्तीफे को वापस लेने की अपील की गई, जिस पर उन्होंने सहमति जता दी। बृहस्पतिवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में गुरुद्वारा श्री माता साहिब कौर दिनेशपुर की मुख्य सेवादार माता कमलेश कौर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें यूपी और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में संगत पहुंची। वक्ताओं ने एक स्वर में हरबंस सिंह चुघ से इस्तीफा वापस लेने की मांग की। रुद्रपुर से पहुंचे ज्ञानी सुरेन सिंह, बिलासपुर से परमजीत सिंह, सितारगंज से गुरसेवक सिंह, जसपुर से जगजीत सिंह भुल्लर, मिलक रामपुर से सुरजीत सिंह, नवाबगंज से मलकीत सिंह, किच्छा से संतोष सिंह, निर्मलसिंह हंसपाल और बाजपुर से पहुंची महक राज सिंह सहित तमाम वक्ताओं ने नानकमत्ता हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की। कहा कि प्रदेश सरकार ने द्वेष भावना के चलते जनहित और सामाजिक में कार्य करने वाली गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब प्रबंधन समिति के पदाधिकारी पर केस दर्ज किया है। इससे सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने पुलिस से प्रशासन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरबंस सिंह चुघ, तराई सिख महासभा के अध्यक्ष प्रीतम सिंह संधू और गुरुद्वारा श्री हरगोविंद सर नवाबगंज के प्रमुख सेवादार बाबा अनूप सिंह पर दर्ज केस को तत्काल रद्द करने की मांग की।

दून अस्पताल में नौकरी के लिए चिकित्सकों को भरना होगा बॉन्ड

देहरादून, एजेंसी। दून मेडिकल कॉलेज, अस्पताल में चिकित्सकों को अब एक निश्चित समय अवधि तक काम करना जरूरी होगा। इसके लिए उन्हें एक बॉन्ड भरना होगा। ऐसे में डॉक्टर निश्चित अवधि के बाद शासन-प्रशासन की अनुमति से ही नौकरी छोड़ सकेंगे। अस्पताल प्रशासन ने शासन स्तर पर इसके लिए कार्ययोजना बनानी शुरू कर दी है। चिकित्सकों के नौकरी छोड़ने से मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है।

दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना का कहना है कि कुछ डॉक्टर बिना किसी विवाद के नौकरी छोड़कर निजी अस्पताल चले जाते हैं। ऐसे में मरीजों का इलाज प्रभावित होता है। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों की सैलरी को लेकर समस्या है। ऐसे में सैलरी बढ़ाई जाने की बात चल रही है। दरअसल, अस्पताल में पिछले छह महीने में कई डॉक्टर नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। इससे मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है। विभागों की व्यवस्था गड़बड़ा गई है।

चिकित्सकों की कमी से सुपर स्पेशलिटी वाले विभाग चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं, कुछ डॉक्टरों ने निराशा व्यक्त करते हुए बताया कि एक डॉक्टर पर अधिक भार डाल दिया जाता है। इससे भी डॉक्टर नौकरी छोड़कर जा रहे हैं।

हल्द्वानी में अब 20.08 हेक्टेयर में बनेगा हाईकोर्ट

हल्द्वानी, एजेंसी। उत्तराखंड गठन के समय वर्ष 2000 में उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल हुई थी। कोर्ट के विस्तार, अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या और पर्यटन स्थल पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए हाईकोर्ट को शिफ्ट करने पर विचार हो रहा था। नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित गौलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट अब 20.08 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की आपत्ति के बाद शासन ने वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव नए सिरे से भेजने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए नोडल अफसर सचिव लोनिवि पंकज कुमार पांडेय ने मंत्रालय की सभी आपत्तियों का निपटारा करते हुए 10 मई तक भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड गठन के समय वर्ष 2000 में उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल हुई थी। कोर्ट के विस्तार, अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या और पर्यटन स्थल पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए हाईकोर्ट को शिफ्ट करने पर विचार हो रहा था। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए गौलापार में 26.08 हेक्टेयर वन भूमि चिह्नित की थी। इस भूमि पर कॉन्सेप्ट ले-आउट प्लान बना कर भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया। लेकिन मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति (आरईसी) ने इस प्रस्ताव पर आपत्तियां लगा दीं। इससे पूरे प्रोजेक्ट पर ही संशय के बादल मंडराने लगे थे। इस दौरान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में लोनिवि की ओर से बताया गया कि प्रोजेक्ट के संबंध में डिजिटल मैपिंग, जियो रिफरेंस मैप, परियोजना के मूल्य की गणना(एनपीवी) और क्षतिपूर्ति पौधरोपण के संबंध में कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके बाद सचिव लोनिवि की अध्यक्षता में पिछले दिनों एक अहम बैठक हुई । बैठक में तय हुआ कि पूर्व में चयनित भूमि 26.08 हेक्टेयर के स्थान पर अब 20.08 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। न्याय विभाग इसका शासनादेश जारी करेगा।

लोहे का गेट गिरा, मासूम बच्ची मौत

बाजपुर, एजेंसी। काशीपुर में चल रहे चैती मेला देखकर नानी के घर आई मासूम बच्ची की लोहे का गेट गिरने से मौत हो गई। मोहल्ले में दर्दनाक हादसा देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। परिजन मासूम बच्ची के शव को अपने गांव ले गए।

बुधवार को यूपी के गांव जोधावाला, रामपुर निवासी प्रीति अपने पति राकेश और बच्चों के साथ काशीपुर चैती मेला देखने गई थी। बाद में बच्चों की जिद के चलते प्रीति अपने पिता बाजपुर के मोहल्ला राजीवनगर निवासी कुंवरपाल के घर अपने मायके आ गई थी। इस दौरान रात करीब साढ़े दस बजे प्रीति की सात वर्षीय बेटी आयशा मकान का गेट खोल रही थी तभी गेट अचानक गिर गया और सात वर्षीय बच्ची गेट के नीचे दब गई जबकि अन्य बच्चे बाल-बाल बच गए। बच्चों की चीक पुकार सुनकर परिवार के लोग दौड़ कर बाहर आए। लोगों ने गेट हटाकर बच्ची को बाहर निकाला। परिवार के लोग आनन फानन में अचेत अवस्था में बच्ची को बाजपुर के रामपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इस

हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। बाद में परिवार के लोग मासूम बच्ची का शव अपने गांव जोधाबाला ले गए। इधर बच्ची की दर्दनाक मौत होने से उत्तराखंड में नानी और यूपी में दादी के घर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। लोगों ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर बच्ची का अंतिम संस्कार यूपी के गांव जोधावाला में कर दिया गया है।

समय से मानसून की उम्मीद, अच्छी बारिश के भी आसार

ऊधम सिंह नगर, एजेंसी।
जीबी पंत कृषि विवि के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आरके सिंह के मुताबिक जून से ला नीनो का प्रभाव शुरू हो जाएगा। इससे मानसून उत्तर भारत में समय से पहुंचेगा। साथ ही इस बार अच्छी बारिश और भीषण ठंड पड़ेगी।

तराई में धूप की तपिश तेज हो रही है। जुलाई से शुरू %%अल नीनो%% प्रभाव के चलते सर्दी भी कम पड़ी और अप्रैल-मई में अमूमन होने वाली बारिश भी नहीं हुई है। अब अल नीनो कमजोर पड़ रहा है। जीबी पंत कृषि विवि के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आरके सिंह के मुताबिक जून से ला नीनो का प्रभाव शुरू हो जाएगा। इससे मानसून उत्तर भारत में समय से पहुंचेगा। साथ ही इस बार अच्छी बारिश और भीषण ठंड पड़ेगी।

उन्होंने बताया कि पिछले साल भारत में मानसून उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसकी वजह अल नीनो का प्रभाव है। मानसून केवल भारत में होने वाली भौगोलिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि यह हिंद महासागर और यहां तक कि प्रशांत महासागर की गतिविधियों से भी प्रभावित होता है। प्रशांत महासागर में अल नीनो मानसून को प्रभावित करता है।

भारत में सर्दी पश्चिम से आने वाली हवाओं से ही प्रभावित होती है। पश्चिम से चलने वाली हवाएं भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश का माहौल बनाती हैं। इससे हिमालय में बर्फबारी होती है और उससे ठंडी हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को ठंडा करने लगती हैं। ला नीनो अल नीनो के विपरीत होता है।

बेरोजगारों को ड्रोन पायलट बनाकर स्वावलंबी बनाएगा इफ्को

काशीपुर, एजेंसी।
ड्रोन के माध्यम से फसलों में स्प्रे कर बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इफ्को की ओर से स्वावलंबी बनाने की योजना शुरू की गई है। बृहस्पतिवार को इफ्को की ओर से इस परियोजना के अंतर्गत चिह्नित किए गए दो युवाओं परिभाष चौधरी निवासी ग्राम गुलगोजी जसपुर और सुमित राणा निवासी ग्राम बक्सर काशीपुर को निशुल्क ड्रोन एवं इन्हें लाने ले जाने के लिए ई-व्हीकल उपलब्ध कराए गए।

इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक नीरज डोभाल ने बताया कि दोनों चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में गुरुग्राम में ट्रेनिंग सेंटर पर 20 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

इसके उपरांत केंद्र सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए। दोनों ड्रोन पायलटों द्वारा ब्लॉक जसपुर तथा ब्लॉक काशीपुर में किसानों के खेतों पर ड्रोन के माध्यम से नैनो उर्वरकों तथा अन्य उर्वरकों का स्प्रे किया जाएगा, जिसमें किसान को केवल 100 से 150 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे भुगतान करना होगा। 100 से 150 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान इफ्को द्वारा ड्रोन पायलट को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्रोन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किसानों के खेतों पर नयी तकनीकी पर बने उत्पादों का स्प्रे करना है। इससे किसानों को लेबर की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। बताया कि आने वाले समय में पांच ड्रोन पायलट का चयन कर उन्हें भी निशुल्क ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर इस प्रोजेक्ट की निगरानी राज्य वितरण प्रबंधक राकेश श्रीवास्तव द्वारा की जाएगी। पूरे उत्तराखंड में इफ्को द्वारा 20 ड्रोन दिए जाएंगे। इफ्को ड्रोन परियोजना के माध्यम से किसानों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार प्रदान करेगी। ड्रोन स्प्रे की बुकिंग किसानों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।